

**राज्य सभा**  
**अतारांकित प्रश्नसंख्या 1406**  
**09 मार्च, 2016 को उत्तरके लिए**

**विदेशों से आयातित इस्पात की मात्रा और मूल्य**

1406. श्री अजय संचेती:

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) गत तीन वर्षों के दौरान विदेशों से आयात किए गए इस्पात के प्रति यूनिट मूल्य सहित तत्संबंधी मात्रा का देश-वार और वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;
- (ख) देश में इस्पात किस मूल्य पर उपलब्ध है;
- (ग) इस्पात का आयात किए जाने के क्या कारण हैं;
- (घ) क्या सरकार का सस्ते आयात से घरेलू इस्पात उद्योग को बचाने के लिए आयातित इस्पात पर प्रभार वसूलने का विचार है; और
- (ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**उत्तर**

**इस्पात और खान मंत्री**

**(श्री नरेन्द्र सिंह तोमर)**

(क) और (ख): ब्यौरे क्रमशः अनुलग्नक -I और II में दिये गये हैं।

(ग): भारत में वर्ष 2014-15 में कुल इस्पात (अलॉय +नॉन अलॉय) के आयातों में लगभग 75.5 प्रतिशत की वृद्धि (वर्ष दर वर्ष) और अप्रैल 15-जनवरी, 16 के दौरान लगभग 24 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इस्पात एक नियंत्रण मुक्त क्षेत्र है और इसका आयात विभिन्न बाजार घटकों यथा कीमत, गुणवत्ता, उपलब्धता इत्यादि पर निर्भर करता है। इसके अतिरिक्त अच्छी गुणवत्ता वाले इस्पात का स्थानीय रूप से उत्पादन नहीं होता है, का भी कुछ ही मात्रा में आयात किया जाता है। आयातों में यह उछाल मुख्य रूप से विश्व स्तर पर इस्पात की अत्यधिक आपूर्ति होने के फलस्वरूप हुआ है। इस कारण से चीन और अन्य देशों द्वारा इस्पात का निर्यात प्रायः उत्पादन लागत से कम मूल्य पर किया जा रहा है।

(घ) और (ङ): सरकार ने घरेलू इस्पात क्षेत्र को सुरक्षा प्रदान करने के लिए विभिन्न उपाय किये हैं जिससे आयातों की वृद्धि दर में गिरावट आई है। जहां वित्तीय वर्ष 2013-14 की तुलना में वित्तीय वर्ष 2014-15 में आयातों में लगभग 75 प्रतिशत की

वृद्धि हुई है, वहीं अप्रैल, 15 - जनवरी, 16 की अवधि के दौरान आयातों में वृद्धि गत वित्तीय वर्ष की समान अवधि की तुलना में कम होकर लगभग 24 प्रतिशत हो गई है। इस संबंध में उठाए गए विभिन्न कदम निम्नकवत् हैं:

- (i) यह सुनिश्चित करने के लिए कि केवल गुणवत्ता युक्ती इस्पात का उत्पादन या आयात हो, सरकार ने इस्पात और इस्पात उत्पाद (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2012, दिनांक 12.03.2012 तथा इस्पात और इस्पात उत्पाद (गुणवत्ता (नियंत्रण) आदेश, 2015, दिनांक 15.12.2015 अधिसूचित किए गए हैं।
- (ii) घरेलू इस्पात उद्योग के लिए कोयला और लौह अयस्क की उपलब्धता बढ़ाने के लिए-  
(क) कोयला ब्लाइक के आवंटन को सरल बनाने के लिए दिनांक 30.03.2015 को 'कोल माईन्स (स्पेलशल प्रोविजंस) एमेंडमेंट एक्ट, 2015 अधिसूचित किया गया है।  
(ख) खनन पट्टे के आवंटन को सरल एवं कारगर बनाने के लिए दिनांक 27.03.2015 को 'खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2015 अधिसूचित किया गया है।
- (iii) केन्द्रीय बजट 2015-16 में फ्लैट और नॉन-फ्लैट दोनों इस्पात पर बेसिक सीमा शुल्की की उच्चतम दर 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 15 प्रतिशत की गई है।
- (iv) इनगॉट्स और बिलेट्स, अलॉय स्टील (फ्लैट एवं लांग), स्टेनलैस स्टीमल (लांग और नान-अलॉय लांग उत्पाद पर आयात शुल्क 5 प्रतिशत से बढ़ाकर 7.5 प्रतिशत किया गया तथा नान अलॉय और अन्य अलॉय फ्लैट उत्पादों पर यह शुल्क 7.5 प्रतिशत से बढ़ाकर 10 प्रतिशत किया गया है। अगस्त 2015 में पुनः संशोधित करके आयात शुल्क 1 फ्लैट स्टील पर 10 प्रतिशत से 12.5 प्रतिशत, लांग स्टील पर 7.5 प्रतिशत से 10 प्रतिशत और सेमी फिनिशड स्टील पर 7.5 से 10 प्रतिशत किया गया है।
- (v) रिबार्स का आयात केवल 'इस्पात उत्पाद गुणवत्ता नियंत्रण आदेश 2012' के अनुसार सुनिश्चित करने के लिए नवम्बर 2014 में निर्देश जारी किए गए थे, ताकि बोरन युक्त रिबार्स के सस्ते आयातों को रोका जा सके।
- (vi) सरकार ने जून, 2015 में स्टेनलैस स्टील के कतिपय किस्मों के हॉट रोलड फ्लैट उत्पादों के चीन (\$ 309 प्रति टन), कोरिया (\$ 180 प्रति टन) और मलेशिया (\$ 316 प्रति टन) से आयातों पर 5 वर्षों के लिए एंटी डम्पिंग ड्यूटी लगाई गई है।
- (vii) सरकार ने सितम्बर 2015 में 200 दिनों की अवधि के लिए 600 एमएम या इससे अधिक की चौड़ाई वाले क्वायलों में नान अलॉय और अन्य अलॉय स्टील के हॉट रोलड फ्लैट उत्पादों पर 20 प्रतिशत का अनन्तिम सुरक्षोपाय शुल्क लगाया है।
- (viii) दिनांक 05.02.2016 की अधिसूचना के जरिये 173 इस्पात उत्पादों पर न्यूनतम आयात मूल्य (एमआईपी) की शर्त लगाई गई है। इस अधिसूचना के तहत शामिल की गई मर्दों का इस देश में आयात अधिसूचित मूल्य से कम पकरने की अनुमति नहीं होगी।